पर उनके लिए स्पेशल स्कूल्स वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो बाल श्रमिकों की समस्या है जिसको आपने शुरू में कहा, वह कानून से ही हल नहीं की जा सकती हैं। कोई मां बाप अपने बेटे को काम पर नहीं भेजना चाहता है; चाय की दुकान पर या कारखानों में नहीं भेजना चाहता है। इस के संबंध में मुख्य समस्या गरीबी है और जब तक उस गरीबी के ऊपर काबू नहीं पाया जाता तब तक बाल श्रमिकों की समस्या इस जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं और उसके लिए सरकार की योजना है कि जो रूरल इम्प्लायमेंट है, जो काम में लगें हुए खेतिहर मजदूर हैं उनकी दशा को सुधारा जाये उनके लिए कोई योजना बनायी जाए; कानून बनाया जाए।

श्री सभापति : उनका प्रश्न है कि जो स्टेट ओन्ड माइन्स हैं क्या उनमें श्रमिक काम कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : वह तो कानून ही निषिद्ध है इसलिए हो ही नहीं सकता। 14 साल से कम उम्र के बच्चे सरकारी नौकरियों या पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में हो ही नहीं सकते हैं।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Minister does not know the fact. In Bhilai in a number of mines owned by public sector undertakings, in their captive mines, children are made to work as a contract labour. I have brought this information to the notice of the Minister.

श्री सभापति : देख लीजिएगा।

श्री राम विलास पासवान : ये कांट्रेक्ट लेबर सिस्टम के संबंध में कह रहे हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे सरकारी नियम के मुताबिक पब्लिक अण्डरटेकिंग्स या सरकारी नौकरियों में रख नहीं सकता है कोई। जहां तक कांट्रेक्ट का सवाल . . .

श्री सभापति : बात सुनिये, यह कह रहे हैं कंट्रेक्ट लेबर के जरिये या भिलाई की जो खदानें हैं उनमें बच्चों को काम पर रखा जा रहा है।

. . . (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उसकी हम जांच करवा लेंगे। माननीय सदस्य बैठे हैं, उसकी जांच करवायेंगे।

श्री सभापति: जांच करवा कर उसको खत्म कर दीजिये। That is all.

Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Development of Growth Centres and Priority Towns in the National Capital Region

*123. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRI MAHENDRA PRASAD:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what steps have so far been taken in pursuance of the National Capital Region Plan for creating growth centres and developing the priority towns; and

(b) the expenditure incurred thereon so far?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) The Regional Plan-2001 for National Capital Region which came into force w.e.f. 23rd January, 1989 does not envisage creation of growth centres in the Region. It has, however, identified the following eight towns/complexes for priority development:

1. Meerut 2. Hapur 3. Bulandshahr-Khurja Complex 4. Palwal 5. Panipat 6. Rohtak 7. Rewari-Dharuhera-Bhiwadi Complex 8. Alwar.

The National Capital Region Planning Board has also prepared an Investment Plan for developent of the Region including the priority towns/compelxes for the 8th Plan.

(b) The expenditure incurred so far on various schemes in the priority towns of Panipat, Alwar, Bhiwadi, Meerut;

Hapur; Bulandshahr-Khurja is Rs. 89.32 crores (including assistance of Rs. 39 crores by the Central Government and the N.C.R. Planning Board).

गुजरात में तिलहनों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

*125. **श्री बलराम सिंह यादव :**
श्रीमती कैलाशपति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जुलाई, 1990 के "फ़ाइनेंशियल एक्सप्रैस" में "आउट लुक फार आयल सीड्स" के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मानसून के अपर्याप्त होने के कारण गुजरात में किसान मूंगफली की खेती के स्थान पर दूसरी फ़सलों के उत्पादन पर जोर दे रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने देश में अगले वर्ष इस कमी को दूर करने के लिये तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कदम उठाये हैं, और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार): (क) जी, हां।

(ख) गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा हुई है जहां खरीफ़ मौसम के दौरान प्रधानतः मूंगफली की खेती की जाती है। तथापि, किसानों ने उपलब्ध आर्द्रता के अनुकूल कम से कम अवधि की आकस्मिक फ़सलों को अपना लिया है ताकि एक अथवा अन्य फसलों को उन्नत किया जा सके।

(ग) सरकार ने आकस्मिक फ़सल प्रणाली का प्रभावशाली ढंग से अनुसरण किया है ताकि तिल की अल्प अवधि वाली तिलहन फ़सल का विस्तार किया जाये, यदि उस क्षेत्र में आर्द्रता उपलब्ध हो। सरकार द्वारा देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने हेतु वर्ष 1990-91 से तिलहन उत्पादन कार्यक्रम नामक एक नई योजना शुरू की गई है। योजना किसानों के लिये महत्वपूर्ण आदानों तथा समर्थन सेवाओं की आपूर्ति करने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। योजना के अगले वर्ष के दौरान भी जारी रहने की संभावना है।

Introduction of Export Special Trains

*127. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether some export special trains are proposed to be introduced very soon;

(b) if so, the details thereof and the names of the stations to be linked under the scheme;

(c) whether these trains would have passenger coaches;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(e) whether these trains would affect the punctuality of other trains; and

(f) if so, the details thereof and the steps to be taken to counter this effect?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) A suggestion has been received from Delhi Exporters Association that railways should run export cargo trains from Delhi and other places in North India to Bombay for transport of non-containerised break bulk cargo, which is at present moving by trurks. The Association has been advised to organise clubbing of their demands for export shipments into a block rake indent and to come forward with concrete proposals in this regard.

(c) No, Sir.

(d) Combining freight and passenger traffic in this case is not desirable.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.